

125

संख्या : - /XXIV(6)/2011

प्रेषक:

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन। | 2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल। |
| 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। | |

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक : 14 नवम्बर, 2011

विषय : राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये निजी विश्वविद्यालय को खोले जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रो0 यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में पारित आदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 68/XXIV(6)/2011 दिनांक 15, मार्च, 2011, दिनांक 28, मार्च 2011, दिनांक 01, नवम्बर, 2011 एवं शुद्धि-पत्र दिनांक 02, नवम्बर 2011 को अतिक्रमित करते हुए उक्त प्रयोजन हेतु नई नीति दो चरणों में निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

निजी विश्वविद्यालय स्थापना की प्रक्रिया दो स्तरीय होगी -

प्रथम चरण - प्रथम चरण में निजी विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर 15 दिन के अन्दर संस्तुति प्रदान की जायेगी। उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर आशय पत्र (Letter of Intent-LOI) जारी करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

द्वितीय चरण - द्वितीय चरण में आशय पत्र की शर्तों के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रस्तावक द्वारा कार्यवाही उपरान्त राज्य सरकार को विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु आवेदन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा दो माह के भीतर प्रस्ताव का परीक्षण कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। विधेयक पारित होने के पश्चात् उसमें उल्लिखित प्राविधान एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय संचालन, छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं पठन पाठन प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रथम चरण

1. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ₹ दस लाख की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पक्ष में देय होगा, जिसे निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। उक्त प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
2. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि वह निम्नांकित में से किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो :-
 - (1) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) या
 - (2) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-02 सन् 1882) या
 - (3) कम्पनी अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-01 सन् 1956) की धारा-25 के अधीन
3. प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
4. यदि प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे।
- 5- निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :-

| क्र०सं० | क्षेत्र | मानकानुसार निर्धारित भूमि | निर्मित क्षेत्र |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | पर्वतीय क्षेत्र | 7.5 एकड़ अधिकतम तीन समीपवर्ती स्थानों (पॉच कि०मी० के भीतर) | 20,000 वर्गमीटर |
| 2. | मैदानी क्षेत्र (जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर) | 10 एकड़ एक साथ एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। | 20,000 वर्गमीटर |

वर्णित आवश्यक भूमि के साथ पाठ्यक्रमों हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के भूमि सम्बन्धी मानक, जो भी अधिक हो, उसका पालन किया जाना प्रस्तावक संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

- 6- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक प्रस्तावकों को, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर, 10 अंक का अधिमान दिया जायेगा।

7- निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (D.P.R.) में निम्नांकित विवरण सम्मिलित किया जायेगा :-

- संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण, संविधान एवं नियमावली ।
- प्रस्तावक संस्था के आय के स्रोत तथा विगत तीन वर्षों की संपरीक्षित लेखा रिपोर्ट (तीन वर्ष से कम अवधि में स्थापित संस्थायें उतने ही वर्षों की संपरीक्षित लेखा उपलब्ध करायेगी, जितने वर्ष उसकी स्थापना के पश्चात् पूर्ण हुए हों (यदि कोई हो))
- प्रस्तावक संस्था की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संमैत्री
- प्रस्तावक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन की दशा में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता, महत्व, लाभ-परिस्थितिक विश्लेषण एवं राज्य के विकास में विश्वविद्यालय का प्रस्तावित योगदान दर्शाते हुए Feasibility Report
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की संदृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं मुख्य कैम्पस (Main Campus) का स्थान
- प्रस्तावक संस्था के प्रवर्तकों (Promoters) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम ₹ 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति (net-worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा-चार्टर्ड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, Wealth Tax Return (प्रवर्तक द्वारा संस्था की चल-अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी।) (इस आशय का शपथ-पत्र)।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित्त के स्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम ₹ 20 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।
- विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण, प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क ढांचा, संक्षिप्त पाठ्य सामग्री एवम् रोजगारपरकता का विवरण।
- प्रस्तावक संस्था द्वारा स्वयं के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों यदि कोई हो, के माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में की गयी कार्यवाही का विवरण ।
- विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एवं अधिकतम 10 एकड़ भूमि मैदानी क्षेत्र अथवा न्यूनतम एवं अधिकतम 7.5 एकड़ भूमि पर्वतीय क्षेत्र

में उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र प्रारम्भ में दिया जायेगा। अधिनियम से पूर्व भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय की घोषणा कि उक्त संस्था एवम् उसके द्वारा संचालित किसी संस्था के विरुद्ध कभी भी कोई दण्डात्मक प्रक्रिया किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं की गयी तथा उक्त संस्था को केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कभी काली सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया।
- प्रदेश के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान रखा जायेगा। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे। यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो राज्य सरकार की अनुमति से उक्त रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।
- निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे।
- प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो, को इस श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे।
- निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय-समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- न्यूनतम ₹ 25.00 लाख की पुस्तकें क्रय करनी अनिवार्य होगी अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रथम तीन वर्षों में न्यूनतम ₹ 75.00 लाख अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो, की धनराशि पत्रिकायें, कम्प्यूटर, नेटवर्किंग आदि मदों में व्यय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- प्रथम वर्ष में न्यूनतम ₹ 30.00 लाख अथवा सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार, जो भी अधिक हो, के उपकरण, फर्नीचर आदि क्रय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक विभाग/डिसिप्लिन में कम से कम एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति शासन/सर्वोच्च नियामक निकाय द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार पारदर्शी तरीके से की जायेगी तथा इनके हित में भविष्य निधि एवं अन्य कल्याणकारी कोषों की स्थापना की जानी अनिवार्य होगी। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित विधेयक में शुल्क, पाठ्यक्रम, सीट इन्टेक, निरीक्षण आदि प्राविधान किये जायेंगे। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. निजी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले प्रस्ताव/प्रस्तावों को पन्द्रह दिनों के अन्दर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मूल्यांकन कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित समिति गठित की जाती है :-

1. अपर सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष
2. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
3. निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी — सदस्य सचिव।

निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा शासन से प्राप्त प्रस्तावों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

9. राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर संस्तुति तथा इस क्षेत्र में नीति निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाती है :-

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------|
| (1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (5) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (6) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| (7) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (8) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (9) कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून | सदस्य |
| (10) दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा | सदस्य |
| (11) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड | सदस्य |
| (12) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल | सदस्य-सचिव |
10. प्रत्येक प्रस्तावक के मूल्यांकन हेतु प्रारूप संलग्न किया गया है, जिसके दो खण्ड हैं :-
- (1) निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन - प्रारूप पत्र-1, इन मदों की पूर्ति होने पर ही अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।
 - (2) प्रस्तावकों का अंकों के आधार पर मूल्यांकन - अंक प्रारूप पत्र-2
 - (3) किसी प्रस्ताव को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही Letter of Intent-LOI की संस्तुति की जायेगी ।
11. Letter of Intent-LOI में प्रमुख रूप से निम्न शर्तों का उल्लेख होगा :-
- (1) भूमि का स्वामित्व मानकों के अनुरूप, भवन एवं अवस्थापना सृजन का प्रमाण ।
 - (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्था (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा किया गया निरीक्षण एवं संस्तुति पत्र ।
 - (3) राज्य सरकार द्वारा सम्पादित निरीक्षण एवं मानकों के बाबत संस्तुति पत्र ।
 - (4) विश्वविद्यालय का शैक्षिक एवं प्रशासनिक ढाँचा ।
 - (5) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी बिन्दुओं पर कार्यपूर्ति का शपथ पत्र ।
 - (6) यू0जी0सी0 अन्य नियामक संस्थाओं, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिनियम, नियम, रेगुलेशन्स तथा शासनादेशों के अनुपालन की पुष्टि ।

द्वितीय चरण -

1- प्रस्तावक द्वारा Letter of Intent-LOI की शर्तों का पालन करते हुए अधिनियम एवं अध्यादेश के आलेख के साथ विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति की जायेगी । ऐसी संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का विधेयक विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा । (विधानसभा सत्र न होने की दशा में अध्यादेश) ।

2- प्रस्तावक के द्वारा द्वितीय चरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उपरोक्त कार्यवाही दो माह के भीतर अंतिम निर्णय किया जाना अनिवार्य होगा ।

3- अध्यादेश/अधिनियम की अधिसूचना निर्गत किये जाने से पूर्व प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा स्थायी विन्यास निधि जो राज्य सरकार के नाम प्लेज्ड होगी, की राशि मैदानी क्षेत्र हेतु ₹ 05.00 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 02.00 करोड़ जो राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी के रूप में देय होगा, शासन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

4- स्थायी विन्यास निधि राजकीय कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम/अध्यादेश अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की जायेगी। अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकेगा।

5- प्रश्नगत नीति से सम्बन्धित कतिपय प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :-

- निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक प्रारूप पत्र-1/भाग-1,
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन अंक पत्र प्रारूप-2/भाग-2
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन संकलित मूल्यांकन तालिका।

6- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

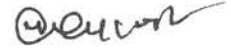
संख्या: TC.68 /XXIV(6)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली-110021।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या:4/2/XXII/XXI/2011-सी0एस0 दिनांक 30,अक्टूबर 2011 के क्रम में सूचनार्थ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।

11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
- ✓ 12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(डॉ० निधि पाण्डेय)

अपर सचिव।

शासनादेश संख्या : Te. 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 14 नवम्बर 2011 का संलग्नक -
उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in
Uttarakhand

निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक

प्रारूप पत्र-1/भाग-1

संस्था का नाम-

निजी विश्वविद्यालय का नाम-

| क.सं. | मानक/बिन्दु | हाँ/नहीं | अभ्युक्ति |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | प्रस्ताव/विस्तृत योजना रिपोर्ट (DPR) के साथ रु0 10.00 लाख प्रोसेसिंग जमा किया गया है | | |
| 2 | प्रस्ताव शिक्षण, शोध, परीक्षाओं तथा प्रसार सेवाओं के लिये समुचित सुविधाओं से युक्त एकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये है। | | |
| 3 | निजी विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर स्थापित/ संचालित होगा, प्रस्तावक द्वारा प्रथम चरण में मुख्य परिसर स्थापित करना प्रस्तावित है (यू.जी.सी. द्वारा 05 वर्ष के बाद दूसरा Campus/Centre स्थापित करने का प्राविधान है)। | | |
| 4 | प्रस्तावक/प्रायोजक निम्नांकित में से एक है : क: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था/ सोसायटी ख: भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट ग: कम्पनी अधिनियम 1956 में धारा-25 अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी की प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण/नवीकरण की तिथि, नियमावली के आधार पर) (क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, शोध, बौद्धिक क्षमताओं के संवर्द्धन आदि विशेषज्ञता क्षेत्रों में योगदान/पहल करना संस्था के उद्देश्यों में वर्णित है)। यदि प्रवर्तक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे। परन्तु इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं। | | |
| 5 | प्रस्ताव द्वारा UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 में वर्णित प्राविधानों/मानकों व प्रक्रिया का अनुपालन करने प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है (शपथ-पत्र संलग्न)। | | |
| 6 | प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति का अनुपालन, स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण, शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट एवं समूह ग व घ के सभी पदों पर नियुक्ति व अन्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है (शपथ-पत्र संलग्न)। | | |
| 7 | भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों, उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं द्वारा प्रायोजक/प्रस्तावक या संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को प्रतिबन्धित नहीं किया गया (शपथ-पत्र संलग्न)। | | |
| 8 | प्रायोजक/प्रस्तावक, संस्था या इसके किन्हीं सदस्यों अथवा संचालित संस्थाओं के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराधिक वाद विचाराधीन नहीं है या दण्ड दिया गया है (शपथ-पत्र संलग्न)। | | |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9 | संस्था के प्रस्तावकों/संस्था के प्रवर्तकों/प्रायोजक संस्था (जिसमें कम्पनी, ट्रस्ट, सोसायटी/संस्था के सदस्यों की व्यक्तिगत की net-worth) सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रु0 30.00 करोड़ न्यूनतम शुद्ध सम्पत्ति (net-worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा-चार्टर्ड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस, शीट, Wealth Tax Return आदि प्रस्ताव के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा। (प्रवर्तक द्वारा संस्था की चल-अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी।) (शपथ-पत्र संलग्न)। | | |
| 10 | प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्राविधान एवम् वित्त के स्रोतों का विवरण। प्रस्तावक संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम धनराशि 20 करोड़ रुपये जमा होना आवश्यक होगा। | | |
| 11 | प्रवर्तक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। यदि प्रवर्तक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे परन्तु इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं। | | |
| 12 | प्रस्तावक को न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रस्ताव करना होगा, इससे कम वाले प्रस्तावों को विश्वविद्यालय स्थापना की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। | | |
| 13 | प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए0आई0सी0टी0ई0 अथवा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण किया जाना एवं अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निजी विश्वविद्यालयों की कोई भी शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम एवं विनियम के प्राविधानों से असंगत नहीं होगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा (सहमति पत्र प्रस्तुत है, जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)। | | |
| 14 | प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। (शपथ-पत्र संलग्न) | | |

संस्तुति :

- (1) प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।
- (2) प्रस्ताव स्वीकार किये जाने हेतु संस्तुति :- प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण किया गया है। अतः भाग-2 के मूल्यांकन हेतु पात्र है।



(डॉ० निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।

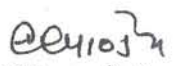
शासनादेश संख्या : १८६४/xxiv(6)/2011 दिनांक 14 नवम्बर, 2011 का संलग्नक -

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन
Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand

अंक पत्र प्रारूप-2/भाग-2

| क्र. सं. | मानक/बिन्दु | निर्धारित अंक | प्राप्तांक |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि (अधिकतम निर्धारित अंक-25) | | |
| | प्रस्तावक संस्था में न्यूनतम 60 प्रतिशत कार्यकारी सदस्य ख्याति प्राप्त शिक्षक, शिक्षक प्रशासक, उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी एवं बुद्धिजीवी सदस्य हैं। | 60-75 प्रतिशत | 05 |
| | | 76-90 प्रतिशत | 07 |
| | प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव-विश्वविद्यालय संचालन अनुभव | 05 से 10 वर्ष | 06 |
| | अथवा | 10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम | 10 |
| | | 15 वर्ष से अधिक | 12 |
| | प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव-महाविद्यालय/संस्थान संचालन अनुभव | 06 से 10 वर्ष | 03 |
| | | 10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से कम | 06 |
| | | 15 वर्ष से अधिक | 08 |
| | प्रस्तावक द्वारा पूर्व से संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर NAAC, NBA से रैंकिंग/ग्रेडिंग प्राप्त है। | A | 06 |
| | | B | 04 |
| | | C | 02 |
| 2 | शैक्षणिक सहयोग समझौता (अधिकतम निर्धारित अंक-05) - | | |
| | उच्च शिक्षा/मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संवर्द्धन-शोध व विकास के क्षेत्र में प्रत्यानित ग्रेड प्राप्त संस्थाओं से शोध, पाठ्यक्रम, शिक्षक व विद्यार्थी अदला-बदली आशय का समझौता (MoU/Tie-up) है। समझौता (MoU/Tie-up) ऐसे विश्वविद्यालय से किया जायेगा, जो शासकीय मान्यता प्राप्त प्रत्यानित करने वाली संस्था द्वारा प्रत्यानित/ग्रेड किया गया हो। | प्रदेश स्तर पर | 02 |
| | | राष्ट्रीय स्तर पर | 04 |
| | | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर | 05 |
| 3 | विश्वविद्यालय का मुख्यालय (मुख्य परिसर) पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान (अधिकतम निर्धारित अंक-10) | | 10 |
| 4 | विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था (अधिकतम निर्धारित अंक-30) | | |
| | प्रस्तावक संस्था के प्रवर्तक/प्रायोजक की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रु० 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति(net-worth)कम से कम तीन वर्षों का | 30.01 से 50 करोड़ | 05 |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | प्रमाण। (संपरीक्षित लेखा रिपोर्ट, बैलेंस शीट तथा Wealth Tax Return आदि) | 50.01 से 75 करोड़ | 10 |
| | | 75 करोड़ से अधिक | 14 |
| | प्रस्तावित विश्वविद्यालय की समस्त चरणों की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित्त के स्रोतों का विवरण। न्यूनतम रु0 20 करोड़ संस्था के बैंक खाते में जमा होना अनिवार्य है। | 20 से 40 करोड़ | 08 |
| | | 40.01-50 करोड़ | 12 |
| | | 50 करोड़ से अधिक | 16 |
| 5 | विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति। (अधिकतम निर्धारित अंक-05) | | |
| | प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के क्षेत्र में तथा उद्योग प्रायोजित पाठ्यक्रमों हेतु न्यूनतम रु0 100 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले औद्योगिक संस्थानों से समझौता (MoU/Tie-up) है। | | 05 |
| 6 | विश्वविद्यालय की राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्ति प्रतिबद्धता (अधिकतम निर्धारित अंक-10) | | |
| | प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति, स्थायी निवासियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण तथा शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट। (शपथ पत्र प्रस्तुत है, जिसे एकट में शामिल किया जायेगा। इन सभी मदों में न्यूनतम आरक्षण/छूट देने पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।) | 26 से 30 प्रतिशत | 04 |
| | | 30 प्रतिशत से अधिक एवं 40 प्रतिशत तक | 06 |
| | | 40 प्रतिशत से अधिक | 10 |
| | | 50 प्रतिशत तक | |
| 7 | प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता (अधिकतम निर्धारित अंक-20) | | |
| | प्रस्तावक द्वारा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। (जिसे एकट में शामिल किया जायेगा) | 06-07 विभागों/विषयों तक | 04 |
| | | 08-09 विभागों/विषयों तक | 06 |
| | | 10 या अधिक विभागों/विषयों में | 08 |
| | व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को अधिमान (जिसे एकट में शामिल किया जायेगा) | 02 पाठ्यक्रम | 05 |
| | | 03 पाठ्यक्रम | 07 |
| | | 04 या अधिक पाठ्यक्रम | 12 |
| | | | |


 (डॉ० निधि पाण्डेय)
 अपर सचिव।

शासनादेश संख्या : TC 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 का संलग्नक -

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन
Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand
संकलित मूल्यांकन तालिका

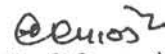
संस्था का नाम-

निजी विश्वविद्यालय का नाम-

| क. | मानक/बिन्दु | निर्धारित अंक | प्राप्तांक |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1 | प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि | 25 | |
| 2 | शैक्षणिक सहयोग समझौता | 05 | |
| 3 | मुख्य परिसर पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान | 10 | |
| 4 | विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था | 30 | |
| 5 | विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति। | 05 | |
| 6 | विश्वविद्यालय की स्थापना में राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता | 10 | |
| 7- | प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता | 20 | |
| | योग | 105 | |

(न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले प्रस्ताव को ही निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति पत्र (LoI) जो अधिकतम तीन वर्षों के लिये मान्य तथा इसके पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगा, राज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

समिति का निर्णय-


(डॉ० निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।